



एनएमसीजी ने 2100 करोड़ रुपये के बराबर की सीवेज उपचार परियोजनाओं को मंजूरी दी

Posted On: 08 APR 2017 9:00PM by PIB Delhi

नमामी गंगे कार्यक्रम को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 2154.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह राशि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एवं दिल्ली राज्यों में प्रति दिन 188 मिलियन लीटर (एमएलडी) (लगभग) की नई सीवेज उपचार क्षमता के सृजन, वर्तमान एसटीपी क्षमता के 596 एमएलडी का पुनर्वास, वर्तमान एसटीपी क्षमता के 30 एमएलडी का उन्नयन, अवरोधन एवं डायवर्जन कार्यों तथा 145.05 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क पर खर्च की जाएगी। मंजूर की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. नई एसटीपी क्षमताका सृजन एवं आई एवं डी कार्य :

क्रम संख्या	परियोजना शहर का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	एसटीपी क्षमता (एमएलडी)
1	हरिद्वार (जगजीतपुर एवं सराय)	273.37	82
2	जोशीमठ	48.43	3.78
3	रुद्रप्रयाग	13.15	0.525
4	कर्णप्रयाग	12.09	0.15
5	कीर्तिनगर	4.23	0.6
6	ऋषिकेश	158.01	27
7	मुनी की रेती	80.45	12.5
8	चमोली, गोपेश्वर	61.63	4.37
9	बद्रीनाथ	18.24	1.01
10	श्रीनगर	22.51	1
11	नंदप्रयाग	6.46	1.5
12	रामनूना, वाराणसी	150.95	50
13	राजमहल	50.23	3.5
	कुल	899.75	187.935

1. वर्तमान एसटीपी क्षमता का पुनर्वास :

क्रम संख्या	परियोजना शहर का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	एसटीपी क्षमता (एमएलडी)
14	जगजीतपुर ,हरिद्वार	14.60	27
15	वृन्दावन	33.82	5
16	ओखला, दिल्ली	665.78	564
	कुल	714.2	596

III. वर्तमान एसटीपी क्षमता का उन्नयन :

क्रम संख्या	परियोजना शहर का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	एसटीपी क्षमता (एमएलडी)
17	तपोवन, ऋषिकेश	2.19	3.5
18	उत्तरकाशी	10.03	2
19	सराय,हरिद्वार	9.63	18
20	स्वर्गआश्रम	4.52	3
21	श्रीनगर-गढ़वाल	15.41	3.5
	कुल	41.78	30

1. आई एवं डी कार्य :

क्रम संख्या	परियोजना शहर का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
22	जगजीतपुर, हरिद्वार का ए,बी,सी,डी, ई जोन	85.14
23	सराय, हरिद्वार में जोन एफ	31.46
	कुल	116.6

1. सीवरेज नेटवर्क :

क्रम संख्या	परियोजना शहर का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	नेटवर्क (किलो मीटर)
24	करमालीचक, पटना	277.42	96.54
25	कौडली में राइजिंग मेन्स का विस्थापन	59.13	8.14
26	भारत नगर से पीतमपुरा तक राइजिंग मेन्स	45.40	6.16
	कुल	381.95	145.05

नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण किया जाता है। इन परियोजनाओं के संपन्न होने से गंगा नदी पर प्रदूषण बोझ में कमी लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अनुपचारित उत्प्रवाही का निस्सरण गंगा नदी में प्रदूषण के बड़े स्रोतों में एक है।

वि.लक्ष्मी/एसकेजे/एनआर- 969

(Release ID: 1487351) Visitor Counter : 7